'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.01.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 4 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 जनवरी, 2018

आरक्षण बचाओ रैली दिल्ली में सम्पन्न

परिसंघ के बैनर तले लाखों की संख्या में दलित हुए एकत्रित

जब तक अधिकार नहीं मिलते, संघर्ष जारी रहेगा : डॉ. उदित राज

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 2017।

अनुसूचित जाति/ जनजाति /पिछड़ा वर्ग संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में आरक्षण बचाओ महा रैली सम्पन्न हुई। जिसमें दलितों-आदिवासियों और पिछड़ों सहित लाखों की संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। बड़ी रैलियां करने का परिसंघ का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन यह रैली स्वयं में इतनी बड़ी थी कि अब तक हुई सभी रैलियों के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए। रैली के कारण कई घंटे तक रामलीला मैदान के आस-पास का क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहर की मुख्य सड़के जाम रहीं। इस बार रैली 26 दिसंबर 2017 को आयोजित की गयी थी। इसके पहले 23, 24 एवं 25 दिसंबर को छुट्टी होने के कारण सुदूर राज्यों से आने वाले लोग 23 दिसंबर से ही डॉ. अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली पर एकत्रित होना शुरु हो गए और 27-28 दिसंबर तक जमे रहे। डॉ. अम्बेडकर भवन में जगह कम पड़ रही थी तो पीछे के पूरे मैदान में टेंट लगाकर लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया। इस बार की रैली में लगभग 8 हजार लोग डॉ. अम्बेडकर भवन में ही ठहरे और खाने-पीने की व्यवस्था की गयी। जब इन लोगों ने डॉ. अम्बेडकर भवन से रामलीला मैदान की तरफ कूच किया तो सड़क पर अन्य वाहनों को कई घंटों तक मौका ही नहीं मिला।

अपार जन समूह को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज

26 दिसंबर को रामलीला मैदान ही नहीं बल्कि उसके आस-पास की सभी सड़कें उस दिन नीली हो गयी थी। जहां भी नजर दौड़ाओ चारों तरफ परिसंघ के ही झंडे और टोपियां नजर आ रही थी। इसी प्रकार की रैलियां और प्रदर्शन यदि सभी प्रदेशों की राजधानियों में पहले ही करके अपनी ताकत दिखायी गयी होती तो निश्चय ही अभी तक कुछ हरकत सरकारों में जरूर हुई होती।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार निजीकरण की आड़ में आरक्षण को समाप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछड़े और दलित हजारों वर्षों से शोषित और वंचित रहे हैं। आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं लेकिन इन वर्गों की जिन्दगी में विशेष परिवर्तन नहीं हो सका है। यह दुर्भाग्य है कि भारत में सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी सर्वाधिक असमानता है। जो अमीर हैं वह अमीर होते जा रहे हैं और बहुमत में लोग या तो बेरोजगार हैं या ठेके पर कम से कम वेतन पर काम कर रहे हैं। सरकारी विभाग में रेस लगी है कि रोजगार एवं काम को ठेका पर दे दिया जाये या आउटसोर्स कर दें। इसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर दलित-आदिवासी और पिछड़ों पर पड़ा है। कोई भी जनतांत्रिक सरकार हो, यह मान कर चला जाता है कि उसका चरित्र कल्याणकारी होगा और प्राथमिकता सबसे ज्यादा अपने नागरिकों को रोजगार देने की है।

डॉ. उदित राज ने विशाल रैली में बोलते हुए कहा कि आरक्षण को विकास का अवरोध माना जाता है जबकि यह गलत है । मद्रास में आरक्षण 1921 में, मैसूर और त्रावणकोर में 1935 और कोल्हापुर रियासत में 1902 में लागू हुआ और ये राज्य उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में विकास के कई सूचकांक में आगे हैं। अब समय आ गया है कि तथाकथित सवर्ण भाई और बहन विचार करें कि हम भी उन्ही के समाज का हिस्सा हैं। जैसे अश्वेतों के साथ अमेरिका में गोरों ने किया। इनकी विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी से देश प्रगति करेगा। यह कभी नहीं संभव है कि लगभग 20 प्रतिशत आबादी की क्रय-शक्ति के बल पर उत्पादन और मांग को बढ़ाया जा सकता है। इन लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो आय बढ़ेगी और क्रय शक्ति भी। जब वस्तु और सेवा की मांग बढ़ेगी तब कुल घरेलू सकल उत्पाद में उछाल आएगा और व्यापारियों को भी फायदे होंगे। जो मेरिट की मिथ्या है कि आरक्षण से निकम्मापन का जन्म होता है वह गलत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अश्वनी देश पाण्डे ने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक शोध किया कि आरक्षण से सरकार में क्या असर पड़ता है तो पाया कि प्रतिकूल तो कतई नहीं लेकिन जहाँ दलित-आदिवासी कर्मचारी ज्यादा थे वहां उत्पादकता में इज़ाफा ही हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बिलकुल उचित है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए । डॉ. उदित राज ने संसद में निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया है और सरकार से अनुरोध है कि उसे सरकारी बिल में परिवर्तित करके कानून बनाया जाये ताकि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सके।

निजीकरण की शुरूआत से अजा/जजा वर्ग के लोग शासन-प्रशासन से ही नहीं, परन्तु आर्थिक और शिक्षण क्षेत्र में भी वंचित हो रहे हैं। इस वंचित होने का एक अहम कारण देश की न्याय प्रणाली है। बेरहमी से विधायिका द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को न्यायपालिका छीन लेती है। उदाहरण के तौर पर 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन वाजपेयी सरकार लायी थी। 85वां संवैधानिक संशोधन पदोन्नति में आरक्षण के लिए किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी और 2006 में इसका निर्णय आया जो नागराज केस के नाम से जाना जाता हैं। पांच जजों की पीठ ने इस संवैधानिक संशोधन को वैध माना था लेकिन इसमें कुछ अनुचित शर्तें भी

शेष पृष्ठ 2 पर

रैली में डॉ. उदित राज के साथ खड़ी उनकी पत्नी श्रीमती सीमा राज व उनके दाएं आर-के. कलसोत्रा, सीताराम बंसल व अन्य एवं बाएं नरेन्द्र चौधरी, परम हंस प्रसाद, सामूभाई वाधेला, सविता कदियान पवार, सत्य प्रकाश जरावता, इंजीनियर जुगल किशोर वाधेला, संजय कांबले, पी.बाला. के. महेश्वर राज, एस. करुपइया, सिद्धार्थ भोजने, तरसेम सिंह बास, वाई.के. आनंद, बाबू लाल व पिछली पंक्ति में शिवचर पासवान, ज्ञान सिंह, जी.आर. नायक, उत्पल कुलकर्णी, हर्ष मेश्राम, अशोक लोहेरिया, साधु सिंह व अन्य

पृष्ठ 1 का शेष

आरक्षण बचाओ रैली .....

लगा दी थी, जैसे – पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जांच, पिछड़ापन और प्रशासनिक दक्षता पर असर न पड़ता हो। जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है, यह तभी साबित हो जाता है, जब अजा/जजा वर्ग के लोगों को संविधान की धारा 341 और 342 के तहत लाया जाता है, जिसका परीक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा किया जाता है। भारत सरकार में लगभग 150 सचिव हैं जिसमें 2-4 ही दलित और पिछड़े समाज से होंगे तो प्रतिनिधित्व की बाहुल्यता क्या भारी कमी है। दिसम्बर 2012 में राज्यसभा में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बिल पास हुआ लेकिन लोकसभा में असफल रहा । आज की रैली में प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार इसी सत्र में बिल लाकर के पास करे ताकि पदोन्नति में आरक्षण की सारी अड़चने दूर की जा सकें।

ठेकेदारी प्रथा की वजह से मजदूरों का शोषण बेइंतहा होता है। अध्यापक, कर्मचारी, चपरासी और मजदूर कोई भी हो। निजी क्षेत्र में नकदी द्वारा वेतन और मजदूरी दी जाती है। जो कागज में तो पूरा दिखाया जाता है परन्तु वेतन का भुगतान आधा-अधूरा ही किया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा चेक या डिजिटल भुगतान से शोषण रुकेगा और इसका सर्वाधिक लाभ दलित आदिवासियों को मिलेगा ।

रैली को विभिन्न प्रदेशों से आए परिसंघ के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

परिसंघ की प्रमुख मांगे :-

1. पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण
2. सरकारी नौकरी में ठेकेदारी प्रथा एवं आउटसोर्सिंग बंद किया जाये
3. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
4. आरक्षण कानून बनाओ
5. सेना और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण ।
6. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
7. समान शिक्षा एवं भूमिहीनों को भूमि
8. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
9. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी
10. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
11. जम्मू व कश्मीर में धारा 370 हटाया जाए और आरक्षण लागू हो
12. दिल्ली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में आवंटित भूमि का मालिकाना हक
13. बैंक की प्रत्येक शाखा दलित-आदिवासी को लोन दें ताकि स्टैंड अप इंडिया सफल हो ।
14. प्रक्युमेंट पालिसी को सही मायने में लागू किया जाये ।
15. एससी/एसटी हब को लागू किया जाये ।
16. रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए जगह दी जाये ।

रैली को सफल बनाने हेतु जिन प्रमुख लोगों ने योगदान दिया वे हैं –

दिल्ली से ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, सबीर खान, विजेंद्र यादव, एम.एस. लाकरा, देवी सिंह राणा, एन.डी. राम, संजय राज, सी.पी. सोनी, डॉ. राज पाल, सत्य नारायण, इन्द्रेश सोनकर, भानू पुनिया, रविन्द्र सिंह, वाई. के. आनंद, आर. एस. हंस, हरि प्रकाश, बाबू लाल, राम कुमार, सागर यादव, एस.पी. वर्मा, सुदेश यादव, मनीष सुर्यवंशी, मुकेश कुमार, दयानन्द, महेन्द्र सिंह, करम चंद, दयाराम, रविन्द्र काटारिया, खेम चंद, विनोद राजौरा, सत प्रकाश, अशोक कुमार, विजेन्द्र सिंह, बाबू लाल, एम. आर. चौधरी, धरम सिंह, बी. पी. सिंह, ओम कार सिंह, डॉ. आर.के. गोविल, देवेन्द्र, विजय, सुशील खटीक, सुमित कुमार, मदन लाल, कौशलेन्द्र कठेरिया, राम नाथ, फकीर चंद, आर. के. वरुण, हेंमत कुमार (आईजीएल), संजीव दोहरे, शशांक, डॉ. एस.एल. सागर, विजय केन, संजय, प्रदीप (भीम आर्मी), तरसपाल तोमर, कलीराम तोमर, जय कुमार, रामनिवास चंद्रवशी, आनन्द, हरिदास वाल्मीकी, मुकेश पहलवान, डॉ. चांद राम आर्या, राम विलास राम, बाबू लाल बूसवाला, धरम पाल भिलवारे, चून्नी लाल, अशोक अहलावत, अशोक लुहेरा, भुपेन्द्र सिंह किरार, बुद्ध रतन,

परिसंघ महिला प्रकोष्ठ से सविता कादियान पंवार, सुनीता केन, सुनीता गोला, उर्मिला कच्छप, संगीता रवि, उषा मधुसूदन, ममता गेडाम, फुलमती, राजकुमारी, सुनीता केन हरियाणा, सरिता सिंघल, महालक्ष्मी, रिंकी सागर, रजनी डांगी, पुष्पा कोली, आशा वर्मा, रेनु सैनी, रेखा, रिटा सरकार, रमा, ललिता, डॉ. रूचिता पाल, कमलेश कुमारी, अंजुम खान, बाबीता किलसन, गीता आसिवाल, गौरी अभीपुरिया, ममता राणी, सैफाली, डॉ. डी. सी. बरूवा,

हरियाणा से सत्यप्रकाश जरावता, विश्वनाथ, महासिंह भूरानिया, सत्यवान भाटिया, राजेंदर जोगपाल, राजेंदर कुमार, डॉ. शिवकुमार, महेश दत्त, वजीर सिंह मेहरा, राजकुमार, डॉ. मुख्तियार सिंह, साधू सिंह, आशीष भुकल, प्रो. रवि महेंद्र, सुनीता कैन, दिलीप जाटव,

उत्तर प्रदेश से सुशील कमल, नीरज चक, आर.के वर्मा, डी.के सिंह, कल्पेंद्र भारती, राजेश वर्मा, नरेश राज, जय प्रकाश, बलराम चक, भोजराज, हरी किशन भारती,

छत्तीसगढ़ से हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे, सी.आर. जगडे,

महाराष्ट्र से सिद्दार्थ भोजने, संजय काम्बले, सुनील जोडे, चंद्रशेखर डोंगरे, उद्धव मूले, जीवन रामटेके, जुगल किशोर बघेल, जी.एल बलाई, हर्षवर्धन दवने, बालाजी कोंडामंगल, रवि सुर्यवंशी, संघरत्न निवडंगे, अजित काम्बले, स्वप्निल काम्बले, प्रो. सतिश वागरे, गणेश येरेकर, प्रकाश दीपके, मंगेश गाडगे, अभिजीत वाघमारे, दिनेश भगत, अक्षय मनवर,

कर्नाटक से जे. श्रीनिवालू, थिप्पेस, संतोष लोहार, शिव काम्बले, सुनील वाघमारे, प्रकाश भंगरे, उत्तर सुतार,

तमिलनाडु से एस. करुपइया, डी. रविचंद्रन, के रविचंद्रन, पी.एन. पेरुमल, श्रीनिवासन, सी.टी प्रभाकरन

वेस्ट बंगाल से पी. बाला, सुब्राता बातुल, सदन नस्कर, मनीमोहन बिश्वास, हरी भाई, सचित कुमार दास,

जम्मू-कश्मीर से आर.के कल्सोत्रा, बी.एल भारद्वाज, नाज़िर चौधरी,

पंजाब से तरसेम सिंह घारू, रोहित सोनकर, नरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह,

केरला से के.टी जोंसन, श्रीमती जोसफ,

मध्य प्रदेश से परम हंस प्रसाद, विपिन टोप्पो, नरेन्द्र चौधरी, आशीष रायपुरिया, एच.आर चौहान, सुरेश कुमार राजौरा, जी.पी. नन्हेट बौद्ध, प्रताप सिंह अहिरवार, सचिन पटेल, राजेन्द्र नरगांवे, प्रकाश अहिरवार, बंटी अहिरवार, सुशील बरखने, दिनेश कुमार,

उत्तराखंड से विजय राज अहिरवार, हीरा लाल, सी. पी सिंह, महावीर सिंह, नीतीन लामीयान,

गुजरात से रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी, एन.जे परमार, बाबूलाल खटीक,

आंध्र प्रदेश से बी दास,

तेलंगाना से के. महेश्वर राज,

ओडिशा से आलेख मलिक, दिलीप कुमार बेहेरा, नारायण दास, जी.आर. नायक, प्रबीर पात्रो, अभिराम नायक, सोनू अनुगु,

हिमाचल प्रदेश से सीताराम बंसल, विकासदीप,

मणिपुर से मधुचन्द्र, रेव लंघू हिलेरी,

झारखण्ड से मधुसूदन कुमार, वेल्फ्रेड केरकेट्टा, जगाराम, पंकज पासवान, उर्मिला कछप, संगीता रवि, डी.पी. लाला, अनिल कुमार,

बिहार से मदन राम, शिवधर पासवान, शिवपूजन, भागीरथी राम, अजय पासवान, अमर ज्योति, विकास कुमार,

राजस्थान से मुकेश मीना, एम.एल रासु, पंचम राम, नन्दलाल बौद्ध, सौरभ महामना, चिरंजीलाल, मनोहर लाल सामरिया, राजेश लोहिया, लक्ष्मण मीणा, लोकेश मेघवाल, रमेश चौहाण, अशोक कुमार, छगन।

***

ये है चमार रेजीमेंट, जिसने लड़ी सबसे खूंखार लड़ाई

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा शासकों के बीच 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध को दलित अपनी अस्मिता के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि उस समय अछूत समझे जाने वाले महार समुदाय के लोग कंपनी की फौज में सैनिक थे। इसी जीत की 200वीं सालगिरह के दौरान पुणे के भीमा कोरेगांव में हुए विवाद में अब पूरा महाराष्ट्र सुलग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों की सेना में एक चमार रेजीमेंट भी थी। जिसे सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए भेजा गया था। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने दो सौ साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजीमेंट में भी देखा जा सकता था। दूसरे विश्वयुद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने थलसेना में चमार रेजीमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ तीन साल ही अस्तित्व में रही।

चमार रेजीमेंट का इतिहास

'चमार रेजीमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी' नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कि कोहिमा में चमार रेजीमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाईयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजीमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया था।

चमार रेजीमेंट थी तो उसे क्यों खत्म किया गया

चमार रेजीमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता आरएस पूनिया बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजीमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजीमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजीमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको आईएनए में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजीमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया। जिन्हें आजादी के बाद रिहा किया गया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधान सभा से विधायक भी रहे। इस रेजीमेंट के दो सैनिक अभी जिंदा हैं। ये हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ के चुन्नीलाल और सोनीपत के धर्मसिंह।

क्या बहाल हो पाएगी यह रेजीमेंट

आजादी के बाद से ही चमार रेजीमेंट बहाल किए जाने की आवाज कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज दबकर रह गई। दलित इस रेजीमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। दलित नेता कहते हैं कि इसे बहाल किया जाय। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था। जिसमें पूछा गया था कि आखिर इस रेजीमेंट को किन कारणों से बंद किया गया। ईश्वर सिंह का कहना है कि दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेता है। उतनी कठिनाई में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत करता हो, फिर भी इनकी रेजीमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शान्त प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजीमेंट की बहाली की मांग की थी। उनका दावा है कि इसी मांग पर नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि 'मामले की जांच करवा रहा हूं'।

रेजीमेंट पर लिखी गई है किताब

हवलदार सुलतान सिंह ने 'चमार रेजीमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी' शीर्षक से किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने 'चमार रेजीमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी' नाम से लिखी। इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजीमेंट हैं।

जेएनयू में रिसर्च

'ब्रिटिश कालीन भारतीय सेना की संरचना में चमार रेजीमेंट एक ऐतिहासिक अध्ययन' विषय पर जेएनयू के मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रहा है। रिसर्चर सतनाम सिंह का दावा है कि यह रेजीमेंट भी उतनी ही बड़ी थी जितनी और जातियों के नाम पर बनी रेजीमेंट।

https://hindi.news18.com/news/delhi/do-you-know-the-history-of-chamar-regiment-of-dalit-fighters-battle-of-koregaon-1218393.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Facebook_HIN

भारत में नहीं थी जाति व्यवस्था और नहीं था कोई चाणक्य - मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से खुलासा

जन उदय : भारत में जातिवाद पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के षड्यंत्र के रूप में विकसित हुई क्योंकि इसका विवरण भारत के पौराणिक इतिहास में कही नहीं मिलता बल्कि इसका प्रमाण ब्राह्मण अपने ग्रंथो में जो दिखाते हैं, वह तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से बोगस है और झूठ है। अपने आपको सर्वश्रेष्ठ और भगवान का प्रतिनिधि बना कर पेश करना और सबसे ज्यादा अधिकार अपने पास रखना और धार्मिक ग्रंथों की रचना कर उनके माध्यम से अपने आपको सभी लोगों पर अत्याचार करने का अधिकार खुद को ले लेना, ये सब षड्यंत्र के रूप में ही सामने आये। इनके द्वारा लिखे गए रामायण, महाभारत झूठे और काल्पनिक ग्रन्थ हैं। अब सवाल आता है भारत में एक वर्ग द्वारा फैलाई जा रही भ्रान्तियों के बारे में। यानी रामायण और महाभारत कभी इस देश में हुए या नहीं या ये सिर्फ कोरी कल्पना है। इतिहास ने भी विज्ञान के नियमों को अपनाया है और इतिहास का लेखन वास्तुनिष्ठ सामग्री पर लेखन के लिए ही जोर डाला गया है, और जब हम वास्तुनिष्ठ सबूतों या सामग्री की बात करते हैं तो उस पर रामायण और महाभारत खरी नहीं उतरती। आइये देखें कि कैसे कहानी रामयाण और महाभारत एक एपिक की तरह लिखे गए जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र तैयार करना था जिसका पहला उदाहरण है।

1. कोई भी वास्तु, शिल्प सबूत नहीं : हर राजा, महाराजा, अपने लिए महल बनवाता है, भवन बनवाता है, बाग बगीचे बनवाता है और इन इमारतों को वह कुछ खास तरीके से बनवाता है, यानी हम अगर सम्राट अशोक का इतिहास देखें तो हमें सभी प्रकार के सबूत मिलते हैं। वास्तु भी और शिल्प भी लेकिन रामायण और महाभारत के इन अभिनेताओं का कुछ भी नहीं मिलता, कुछ संगठनों का कहना है की मंदिर मिले हैं भगवान के, तो कोई इनसे पूछे क्या भगवान इन्हीं मंदिरों से शासन करते थे ?

2 . हर शासक, राजा, महाराजा अपने शासन काल में अपने सिक्के, यानी व्यापार के लिए सिक्के, मुद्रा चलवाता है, जो निश्चित तौर पर उसकी सीमा और विदेश सीमा यानी उसके शासन के बाहर भी खुदाई में मिलते हैं लेकिन रामायण, महाभारत काल का ऐसा कुछ भी नहीं मिलता।

3. विदेशो से सम्बन्ध एक राजा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, युद्ध भी होते है संधिया भी होती है लेकिन इन दोनों काल के, यानी रामायण और महाभारत काल का ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता।

4. विदेशों से व्यापार, यात्रियों के लिए धर्मशाला, सुरक्षा व्यवस्था, बाग बगीचे, सराय, ये सब भी बनवाते रहे हैं लेकिन इन दोनों काल का कुछ भी नहीं मिलता।

5. संस्कृति कला – किसी भी इतिहास में या शासन में अपनी कला और संस्कृति जन्म लेती है, लेखक, कवि आदि जन्म लेते हैं लेकिन न तो किताबों के स्तर पर कुछ मिलता है न ही शिल्प, पेंटिंग, नक्काशी, वाल राइटिंग, वाल कार्विंग, भित्ति चित्र आदि। इस काल का कुछ भी नहीं मिलता।

6. कालखंड : सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी घटना किसी कालखंड में ही होती है यानी उसका अपना एक समय होता है लेकिन इन ग्रंथो का कोई भी कालखंड नहीं है। कहने को तो हर धार्मिक संगठन अपनी-अपनी दलील देता रहता है, कोई कुछ काल बताता है तो कोई कुछ इसके अलावा जो ग्रन्थ या किताबें मिली हैं, उनकी भी कार्बन डेटिंग से कोई सबूत नहीं मिलता कि ये ग्रन्थ बहुत पुराने हैं, बल्कि इसमें भी घपला है। सो विज्ञान धारणा या कल्पना से शुरू हो सकता है लेकिन हमने उड़ने की कल्पना की लेकिन उड़े कैसे ? इसलिए वैज्ञानिक कोई भी तथ्य आज तक नहीं है और न ही आएगा। खैर यहां पर बात चल रही है जातिवाद की तो हम यहां पर किसी भारतीय ग्रन्थ के माध्यम से नहीं बल्कि एक विदेशी सैलानी मेगस्थनीज के माध्यम से ही समझेंगें कि भारत में जातिवाद या जाति का अस्तित्व ही नहीं था। मेगस्थनीज (350 ईसापूर्व – 290 ईसा पूर्व) यूनान का एक राजदूत था जो चन्द्रगुप्त के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ई. पू. भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा, उसका वर्णन उसने 'इंडिका' नामक पुस्तक में किया है। इंडिका में मेगस्थनीज ने भारत में यानी चन्द्रगुप्त के समय में समाज में सात वर्ग बताये। यह बात ध्यान में रहे मेगस्थनीज ने सात वर्ग की बात की है। पहला वर्ग इसमें एक पुरोहित वर्ग बताया जो लोगों को पूजा कराता था और लोगों के पैसे से या समान से अपना जीवन चलाता था लेकिन वह सबसे ऊपर था, ऐसा बिलकुल नहीं था, बल्कि इसको कार्य करने से रोका जा सकता था और वही आदमी फिर समान्य वर्ग में आ जाता था। दूसरा वर्ग किसान का था जो खेती करते थे, तीसरा ग्वाले, का था जो लोग भेड़ बकरियां चराते थे, चौथा वर्ग दुकानदार और शिल्पकारों का था जो दुकान चलाते थे। ये लोग टैक्स अदा करते थे। पांचवा वर्ग सैनिकों का था और सबसे बड़े और इज्जतदार लोग यही होते थे। ये लोग युद्ध करते थे और शांतिकाल में आराम करते थे। छंठा वर्ग सुपरवाइजर का था जो देश समाज में हो रहे हर काम पर निगरानी रखते थे और इन कामों के बारे में राजा को जानकारी देते थे। सातवां और अंतिम वर्ग मंत्रियों का था जो राज्य से सम्बन्धित हर कार्य में राजा से मंत्रणा करते थे और नीतियां बनाते थे। मेगस्थनीज ने एक ही परिवार और वंश में पैदा हुए लोगों को हर तरह के काम करते देखा। यानि कोई भी वेग निश्चित और स्थाई नहीं था। बल्कि योग्यता के अनुसार अपने व्यवसाय को चुन सकते थे। अब चूंकि मेगस्थनीज 3 बी सी में था और जाति नहीं थी तो ब्राह्मण कैसे कामयाब हो गए। इस तरह के समाज का निर्माण करने में और सबसे बड़ी बात की ब्राह्मण ग्रन्थ जिस किसी चाणक्य नाम के विद्वान की बात करते हैं और यह जताते हैं की मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उसका बड़ा हाथ था। दरअसल मेगस्थनीज ने जब दरबार का वर्णन किया तो उसमें भी चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, यानि यह भी एक काल्पनिक किरदार है। वैज्ञानिक रूप से यह बात प्रमाणित है की ब्राह्मण विदेशों से आए, घुमन्तु लोग थे और यहां आकर इन्होंने शरण मांगी जो इन्हें दे दी गई। इन्होंने कई बार इस देश और समाज से गद्दारी करने की कोशिश की लेकिन ये लोग 18 बी सी में कामयाब हो गए। परशुराम / पुष्यमित्र शुंग इसे ब्राह्मण भगवान् भी मानते हैं, क्योंकि इसने मौर्य साम्राज्य को धोखे से समाप्त कर ब्राह्मण शासन स्थापित किया। इसने अशोक के पोते ब्रहद्रथ को धोखे से मार दिया था और लाखों बौध्द लोगों की हत्या की और चौरासी हजार बौध्द विहारों को तोड़ मंदिरों में बदल दिया। यह बात याद रहे कि इससे पहले मंदिर नहीं थे लेकिन लोगों के कुल देवी-देवताओं के पूजा गृह थे। इसके बाद इन्होंने जातिवाद यानी अपने आपको सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए ऐसे ग्रंथो की रचना की, जिनके जरिये देश में असमानता, बर्बरता, आज भी बरकरार है, और इसी कारण देश का सबसे बड़ा वर्ग तरक्की नहीं कर पाया शिक्षित नहीं हो पाया और यही कारण है देश की बदहाली का। .

http://januday.co.in/NewsDetail.aspx?Article=10449

***

मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था क्रिसमस?

आर.वी. स्मिथ

दिल्ली समेत दूसरे शहरों और उनके होटलों में क्रिसमस का जश्न मनाया जाता है। आज की पीढ़ी को यह जानकर हैरानी होगी की मुगल शासक भी क्रिसमस मनाते थे। औरंगजेब और कुछ कठपुतली राजाओं को छोड़ दिया जाए तो अकबर से लेकर शाह आलम तक के मुगल शासकों ने क्रिसमस मनाया है। मध्ययुगीन यूरोप में क्रिसमस का जन्म हुआ था लेकिन उत्तर भारत में इसकी शुरुआत अकबर के समय हुई जिसने एक पादरी को आगरा में अपने राजदरबार में आमंत्रित किया था।

मुगलकाल में आगरा पूर्व का सबसे आलीशान शहर था। दिवंगत लेखक थॉमस स्मिथ ने कहा था कि जो भी यूरोपवासी इस जगह पर आता था वो इसकी गलियों की चकाचौंध, व्यापार की समृद्धि और हार की तरह महलों के साथ सजी यमुना नदी की खूबसूरती को देखकर प्रभावित हो जाता था। वह कहते थे, यह एक महानगर था जिसमें इटली के सुनार, पुर्तगाल और डच के जहाज के मालिक थे। फ्रांस के पर्यटक, व्यापारी और मध्य एशिया एवं ईरान के कारीगरों समेत मध्य पूर्व के विद्वान आगरा का दौरा करते थे। इतने विदेशियों के होने के कारण उन दिनों क्रिसमस एक बड़ी चीज हुआ करता था। फ्रांसिस्कन एनल्स बताते हैं कि एक जनसमूह की खुशी पूरे शहर में फैली रहती थी।

बाजारों में त्योहार की छटा साफ दिखती थी। दिसंबर की सर्द हवा में बाजारों में रंग बिरंगे मेहराब, बैनर और कई देशों के झंडे लहराते दिखते थे। तुरही, शहनाई बजती थी, पटाखे फूटते थे और चर्च का घंटा बजता था। अकबर ने पादरी को शहर में एक भव्य चर्च बनाने की अनुमति दी थी जिसमें कई भारी घंटे लगे थे और उसमें से एक अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल में गिर गया। कोतवाली शहर में इसको एक हाथी भी नहीं ले जा सकता था। यह घंटा जहांगीर के भतीजे के लिए हुए एक भव्य कार्यक्रम के दौरान टूट गया। कहा जाता है कि उस समय चर्च का कर्मचारी खुशी से पागल हो गया था और घंटे को तब तक बजाता रहा जब तक वह टूटकर गिर नहीं गया। सौभाग्य से इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ और कर्मचारी की नौकरी भी नहीं गई। अकबर और जहांगीर इस त्योहार को मनाते थे और आगरा के किले में पारंपरिक भोज मे भाग लेते थे।

क्रिसमस की सुबह अकबर अपने दरबारियों के साथ चर्च आते थे और प्रतीकात्मक रूप से ईसा मसीह के जन्म को दिखाने के लिए बनाई गई गुफा को देखते थे। शाम में हरम की महिलाएं और युवा राजकुमारी लाहौर में चर्च का दौरा करती थीं और मोमबत्तियां पेश करती थीं। अकबर जब हर क्रिसमस पर आगरा के चर्च में आते थे तो उनका स्वागत एक बिशप की तरह होता था, घंटियां बजाई जाती थीं और भजन गाए जाते थे। जो यूरोपवासी मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे और लड़ते थे वो सब कुछ भूलकर इस त्योहार में भाग लेते थे। आगरा और शायद उत्तर भारत उनके लिए क्रिसमस पर खेले जाना वाला खेल लेकर आया। क्रिसमस की रात वह आमतौर से छोटे बच्चे और बच्चियों को परियों के परिधान पहनाकर ईसा मसीह के जन्म का नाटक खेला करते थे। अकबर और जहांगीर के समय नाटक को बेहतर तरीके से आयोजित किया जाता था। नाटक के दौरान शांति बनाए रखने के लिए शाही फौज आती थी क्योंकि बिन बुलाई जनता के कारण प्रदर्शन टूटने का खतरा रहता था। नाटक की रिहर्सल बाजार के इलाके में होती थी जिसे अब फुलट्टी के नाम से जाना जाता है। वहां ब्रिटिश मुख्यालय हुआ करता था।

1632 के बाद नाटक बंद कर दिया गया क्योंकि शाहजहां का पुर्तगालियों से मतभेद हो गया था। हुगली बंदरगाह बंद करने के बाद आगरा में चर्च को तोड़ दिया गया और इसाईयों द्वारा सार्वजनिक प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी गई। उस समय सैकड़ों पुर्तगाली कैदी आगरा में थे जो बंगाल से लाए गए थे। लेकिन 1640 में जब मुगलों और पुर्तगालियों के बीच रिश्ते ठीक हुए तो उन्हें आगरा में फिर से चर्च बनाने की अनुमति दी गई। चर्च अभी भी मौजूद है लेकिन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय तक नाटक नहीं खेला जाता था। रंगीला ने आगरा और दिल्ली में अकबर के समय से रह रहे फ्रांस के बर्बनों और डच लोगों की सहायता की थी। लेकिन कुछ कथित अपमान के बाद बर्बनों ने दिल्ली छोड़ दी और वह भोपाल में बस गए। इसके बाद शाह आलम, अकबर शाह सैनी और बहादुर शाह जफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया। हालांकि, 1940 के अंत तक वो नाटक नहीं खेला जाता था। 1958 में आगरा के पहले भारतीय आर्कबिशप डॉक्टर डॉमिनिक आर्थाइड ने इसे पुनर्जीवित किया। जो अभी अनुपस्थित हैं वे महान मुगल थे, हालांकि आध्यात्मिक रूप से उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। आगरा और चर्च ने उनसे काफी कुछ लिया है।

वैसे आगरा और दिल्ली के बड़े पादरियों के आदेश में उत्साह के साथ क्रिसमस का जश्न मनाने की बात है लेकिन नाटक खेलने की परंपरा को जारी रखने पर ध्यान नहीं दिया गया है। और यह दुख की बात है।

-http://www.bbc.com/hindi/india-42473625?ocid=socialflow_facebook

***

जाति और झगड़ा

भीमा कोरेगाँव की अप्रिय घटना 1 जनवरी 2018 को होती है और उसकी प्रतिक्रिया न केवल महाराष्ट्र के कई जिलों तक होती है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी झकझोर कर रख देती है । जब कभी ऐसी घटनाएं होती है तो क्या राजनैतिक लोग, मीडिया या बुद्धिजीवी सभी अपनी व्याख्या, राय, समाधान देने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो फिर वही मंथन होता है। राजनैतिक पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके बच कर निकलने की कोशिश में रहती हैं। शायद ही प्रयास किया जाता हो कि जाति यक्ष प्रश्न को गंभीरता से संबोधित किया जाये। जाति मिटाने की कोई बात करता नही और चाहते हैं कि इसका प्रभाव भी न हो। इससे बड़ा द्वंद भारत में कुछ हो ही नही सकता। हम दुःख या बीमारी को माने ही न, तो इलाज कहाँ से संभव है और यही जाति के बारे में सच्चाई है।

1 जनवरी 1818 को अंग्रेज और पेशवा के बीच कोरेगाँव में युद्ध होता है, लगभग 500 दलित, ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान फ्रांसिस स्टांटन के नेतृत्व में लगभग 28 हजार पेशवा की सेना से मुकाबला करते हैं और पेशवा को पीछे हटना पड़ता है। इस लड़ाई का जिक्र जेम्स ग्रांट डफ की किताब (अ हिस्ट्री ऑफ दा मराठास) में मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि जाति उत्पीडन की वजह से महार ब्रिटिश फौज का साथ दिये। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में दलित यहाँ इकट्ठा होकर अपना शौर्य दिवस मनाते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इनके पूर्वज अंग्रेजों की तरफ से लड़े फिर भी गर्व की बात है। उस समय पेशवा की रियासत में दलितों को कमर में झाड़ू बाँध करके चलना पड़ता था, ताकि उनके पाँव के निशान सड़क पर न रह जाये जिससे सवर्ण अपवित्र हो जाते। गले में हंडिया बाँध करके चलना पड़ता था ताकि थूके तो बाहर न गिरे। इनकी परछाई से भी सवर्ण अपवित्र हो जाते थे। अगर महार दलित अंग्रेज की तरफ से लड़े तो गलती हमारी जाति व्यवस्था की थी। इतना महा अत्याचार कि मल दृमूत्र को साफ करने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर लेते थे तो क्या उससे भी ज्यादा स्थिति दलितों की खराब थी। सेना में भर्ती होना एक अवसर भी था जो कि सवर्ण उन परिस्थितियों में कभी न देते। भारत के लोग जातियों में बटें थे इसीलिए सिकंदर के बाद से लेकर जितने हमलावर आये उनको साथ मिलता गया और वे जीतते गए। अंग्रेज हम पर शासन किये उसके लिए प्रमुख रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार रही है। अंग्रेजों ने दो निर्णायक युद्ध लड़े एक कोरेगाँव का तो दूसरा क्लायु के नेतृत्व में 1757 में प्लासी का, वहां भी दुसाध, जो अछूत थे उनके सहयोग से अंग्रेज जीते। डॉ. अम्बेडकर कोरेगाँव युद्ध स्मारक की 109 वीं वर्षगांठ में गये थे जिससे इसका महत्त्व और बढ़ गया।

आज जब लाखों की संख्या में दलित हर साल इकट्ठा होते हैं तो उनके पीछे कौन सी सोंच है जो लोगों को प्रेरित करती है वहां आने को। हजारों लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है लेकिन यहाँ पर आसानी से लाखों एकत्रित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार इसके पीछे कहीं ज्यादा है क्योंकि इसके द्वारा दलित आज भी यह एहसास करता है कि भले सवर्णों ने मल-मूत्र से बदतर उन्हें समझा हो लेकिन यह ज्यादती थी और बदले की भावना से शौर्य दिवस मनाते हैं। अगर बदले की भावना न कहा जाये तो यह कह सकते हैं कि अवसर मिलने पर दलित पीछे नहीं हैं। बबूल है तो उसका काँटा भी साथ होगा ही। जाति है तो भेद भाव अन्तर्निहित रहेगा ही। इंसान मशीन नहीं है कि विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार बदल जाये। घर में रहे तो व्यवहार कुछ और, बाहर कुछ और एवं राजनीति में भिन्न, ऐसा एक मुर्ख या चालाक या स्वार्थी ही सोंच सकता है। जाति खाने-पीने, सोने-जागने, शादी-विवाह, जनम-मरण, लेन-देन, संकट, और सुख-दुःख में काम आती है तो सोंच क्या उससे हट करके निर्मित होगी। जाति समाज में है तो राजनीति, व्यापार, नौकरशाही और विभिन्न संस्थाओं में तो जाएगी ही। सच तो यह है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा देश का हो ही नहीं सकता। विकास और मूल भूत सुविधाओं से भी कहीं बड़ा मुद्दा यह है। जब जाति का प्रश्न हल हो जायेगा तो ये समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएँगी। जनतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है लेकिन हमने इस प्रश्न को कभी संबोधित नही किया। न तो राजनैतिक पार्टियों ने और न ही सरकार ने इसका उन्मूलन करने का सोंचा। बुद्धजीवियों के दिवालियापन को क्या कहना। इनको देख कर के लगता है कि बुद्धजीवी की परिभाषा बदल दी जानी चाहिए क्यों कि जब ये कलम उठाते है तो राजनीति का जातिवाद तो दिखता है और जो डाली और पत्ता है लेकिन जड़ नहीं दिखती है जो समाज है। किसी भी पार्टी के एजेंडे में इस समस्या के समाधान की बात ही नहीं तो कैसे बड़ा बदलाव होगा। बौद्धिक ईमानदारी ही नही है तो समाधान कैसे होने वाला है। पहले हम माने कि जाति व्यवस्था खराब है तभी तो हल करेंगे। इनकी बुद्धि पर तरस आती है जब ये हिन्दू समाज की एकता भी चाहते हैं और जाति भी बनाये रखना।

***

आरक्षण बचाओ रैली में सविता कदियान पंवार के नेतृत्व में

महिला प्रकोष्ठ का परचम लहराया

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वावधान में आरक्षण बचाओ रैली का आयोजन 26 दिसंबर 2017 को दिल्ली के रामलीला मैदान मे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ. उदित जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों के लोगों की भागीदारी रही ।

यह रैली एक ऐतिहासिक रैली साबित हुई क्योंकि इस बार की रैली में पहली बार महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी परिसंघ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती सविता कदियान पंवार के नेतृत्व में रही। इस बार की रैली में दिल्ली सहित पूरे देश से महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा था। जिसमें झारखंड प्रदेश से श्रीमती ऊषा मधुसूदन, उर्मिला कच्छप, संगीता जी, महाराष्ट्र से श्रीमती ममता गेडाम, विश्राम तायडे, बिहार से ममता जी, यूपी से श्रीमती रुचि वर्मा, नितिन बौद्ध, अनुसया, फूलमती, राजकुमारी, हरियाणा प्रदेश से संगीता केन, सावित्री जी, तमिलनाडु प्रदेश से महालक्ष्मी जी आदि के साथ विभिन्न प्रदेशों से हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। दिल्ली प्रदेश की कमान श्रीमती सुनीता केम जी ने बखूबी संभाली और पूरी दिल्ली के सभी जिलों से भी महिलाएं रैली मे शामिल हुई जिसमें श्रीमती रिंकी सागर, सुनीता गोला (स्वरूप नगर) पुष्पा कोली, आशा वर्मा, रेणु सैनी (किराड़ी), सुजाता प्रकाश (बवाना), रेखा (शुकुरपुर), रामा (आनंद पर्वत), कमलेश डांगी (खेड़ाखुर्द), सुनीता रेविलिया (करोल बाग), ललिता (शाहदरा), मोनिका सूर्यवंशी (करावल नगर), रीटा सरकार, बबीता किलसन आदि। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को संविधान में बराबरी का अधिकार दिया उसी बराबरी का अधिकार इस रैली में पहली बार दिखा और आज राष्ट्रीय संयोजक सविता कदियान पंवार जी के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ पूरे देश मे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में महिला प्रकोष्ठ एक बड़े स्तर पर पूरे देश में ऐतिहासिक मुकाम तय करेगा।

रैली के मंच से बोलते हुए महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती सविता कदियान पंवार जी ने कहा कि आज पूरे देश में आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है, धीरे धीरे सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब ने महिलाओं को बराबरी का संवैधानिक अधिकार दिया और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, इसकी वजह से ही आज इस लड़ाई में महिलाएं भी आगे हैं । परिसंघ हमेशा से दलितों, वंचितों और महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्ष करता रहा है तो महिलाएं भी इस आरक्षण को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। सविता जी ने रैली में दिल्ली सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों से शामिल होने वाली सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस ऐतिहासिक 20वीं रैली में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया।

- सविता कदियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक
परिसंघ महिला प्रकोष्ठ
मो. 9873944026

***

26 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित आरक्षण बचाओ रैली की झलकियां

महारों और मांगों के हाथों पेशवाई का अंत

आंबेडकर स्वयं एक महार थे और उनका जन्म महू में हुआ था। उनके पिता सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार थे। 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव स्मारक की यात्रा पर गए थे। आज हजारों दलित इस स्मारक पर हर साल इकट्ठा होकर उन महारों के पराक्रम को याद करते हैं जिन्होंने पेशवाओं के अन्यायपूर्ण ब्राम्हणवादी शासन को समाप्त करने में मदद की थी। सन् 1796 में पेशवा बाजीराव द्वितीय, टुकड़ों में बंटे मराठा राज्य के शासक बने। जैसा कि इतिहासकार अनिरुद्ध देशपांडे लिखते हैं, 'आने वाले समय ने यह साबित किया कि वे एक कलंकित पिता के सच्चे पुत्र थे'। उनके शासनकाल (1796-1818) में मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से दो युद्ध किए। इन युद्धों का अंत, मराठा साम्राज्य के अस्त और मध्य व पश्चिमी भारत में ब्रिटिश राज के उदय में हुआ। बाजीराव द्वितीय, पुणे में ब्रिटिश शासकों की कठपुतली भर थे और यह उन्हें रास नहीं आ रहा था। वे चुपचाप षडयंत्र रच रहे थे ताकि वे अंग्रेजों को उस धरती से बाहर खदेड़ सकें , जहां पर उनका और उनके ब्राह्मण पूर्वजों का, लगभग एक सदी से निर्बाध शासन चल रहा था-तब से, जब उन्होंने मराठा भोंसले वंश से सत्ता हथियाई थी। परंतु सन् 1817 में उनके वेतनभोगी सैनिक कमांडर कैप्टन फोर्ड अपनी सैनिक टुकडियों के साथ अंग्रेज रेसीडेंट 'मोंटस्टूआर्ट एलफिन्स्टोन' से जा मिले और उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। वे अपने ब्राह्मण अनुयायियों के साथ अपने पूर्वजों की राजधानी से भाग निकले। उनके ब्राह्मण अनुयायियों को डर था कि पेशवाई के अंत के साथ ही महाराष्ट्र के समाज पर उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने पेशवा और उनकी सेना का पीछा करना शुरू किया और खड़की, यरवदा और कोरेगांव में हुए युद्धों में उसे पराजित किया। खड़की के पास एक पहाड़ी से अपनी सेनाओं को बुरी तरह पराजित होते देखने के बाद, बाजीराव ने युद्ध के मैदान से पलायन कर दिया और वे 'पलपुत्ता' (भगोड़ा) कहलाए। इन युद्धों में से केवल कोरेगांव के युद्ध की याद अभी बाकी है और यद्यपि इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, फिर भी, इस जीत का जश्न भारतीय मनाते हैं। अन्यथा तो हमारे देश में आधिकारिक रूप से केवल ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाता है।

कोरेगांव की लड़ाई

'कोरेगांव मध्यम आकार का एक गांव है, जो बीमा नदी के खड़ी चढ़ाई वाले तट के एकदम ऊपर स्थित है। परंतु चूंकि भारतीय नदियों के पाट बहुत चौड़े होते हैं और बारिश के मौसम के अलावा शायद ही कभी भरते हैं, इसलिए दोनों तटों के बीच के केवल थोड़े से हिस्से में पानी बहता था और गांव, पानी से 50 या 60 मीटर दूर था। वहां एक मिट्टी की दीवार भी देखी जा सकती है, जो शायद पहले गांव के चारों ओर थी परंतु अब वह नदी की ओर कई स्थानों पर टूटी हुई है और पूर्व की तरफ पूरी तरह बिखर चुकी है', बाम्बे नेटिव इन्फेन्ट्री की प्रथम रेजिमेन्ट के कैप्टन जेम्स ग्रांट डफ

(1799-1858) 'ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज' (खण्ड 3) में लिखते हैं। पाद टिप्पणी में वे जोड़ते हैं, 'मैं गांव का यह विवरण केवल अपनी स्मृति से दे रहा हूं। मैं वहां सात या आठ वर्षों से नहीं गया हूं। बल्कि उस सुबह के बाद मैंने वह गांव नहीं देखा है, जिस दिन कैप्टन स्टॉन्टन ने वहां से रवानगी डाली थी। उस समय मैंने उस युद्ध स्थल को ध्यानपूर्वक देखा था परंतु तब मेरा इरादा उसका विवरण प्रकाशित करने का नहीं था'।

"बटालियन वर्ष के आखिरी दिन, रात लगभग आठ बजे, सिरूर से रवाना हुई", डफ लिखते हैं। "उसमें करीब 500 सैनिक थे और 6 पाउंड की दो तोपें थीं, जिन्हें संचालित करने के लिए एक सार्जेन्ट और एक लेफ्टिनेंट के अधीन मद्रास आर्टिलरी के 24 यूरोपियनों का दल भी था। उसके साथ ही हाल ही में भर्ती 300 सैनिकों का घुड़सवार दस्ता भी था। इन सबकी कमान कैप्टन स्टॉन्टन के हाथों में थी। पूरी रात चलने के बाद, नए साल के पहले दिन के लगभग दस बजे सुबह, यह टुकड़ी बीमा नदी के इस पार, कोरीगांम की चढ़ाई पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि नदी के उस पार मराठाओं की पूरी सेना, जिसमें लगभग 25 हजार सिपाही थे, उनका इंतजार कर रही है। कैप्टन ने नदी के तट की ओर बढ़ना जारी रखा और पेशवा की सेना को ऐसा लगा कि उनका इरादा नदी पार करने का है। परंतु ज्योंही वे गांव में पहुंचे उन्होंने वहीं मोर्चा जमा लिया'।

पेशवा की पैदल सेना, जिसमें 'नियमित सैनिकों के अलावा अरब और गोसाई भी शामिल थे' ने गांव पर हमला कर दिया। राकेटों के लगातार हमले से कई घरों में आग लग गई। 'गांव को घुड़सवार और पैदल सैनिकों ने घेर लिया और पहला हल्ला बोलने वाली टुकड़ी की सहायता के लिए और सैनिक पीछे से आ गए। नदी तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया। कैप्टन स्टॉन्टन के पास अब खानेपीने की सामग्री प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था और रात भर चलने से थकी उनकी सेना, बिना खाना या पानी के, कड़ी धूप में फंस गई थी। इसके बाद वह संघर्ष शुरू हुआ, जिसका सामना अंग्रेजों को भारत में कई बार करना पड़ा है। एक-एक फुट जमीन के लिए संघर्ष हुआ। कई गलियों पर कई बार कब्जा करना और छोडना पड़ा।'

पेशवा की सेना के अरब सैनिकों ने एक तोप पर कब्जा कर लिया और एक तोपची को मार गिराया। आधे से अधिक यूरोपियन अधिकारी घायल हो चुके थे और उनके पास उनका दर्द कम करने के लिए एक बूंद पानी भी न था। जो लड़ रहे थे, उनमें से कई पानी की कमी के कारण बेहोश होकर गिरते जा रहे थे। परंतु जल्दी ही स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। एक घायल ब्रिटिश अधिकारी ने देशी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ वीरतापूर्वक तोप पर पुनरु कब्जा कर लिया।'जिन सिपाहियों ने यह काम किया उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। तोप पर पुनरु कब्जा हो गया और एक के ऊपर एक पड़ी अरब सैनिकों की लाशें इस बात का सुबूत थीं कि तोप को बचाने के लिए कितना जबरदस्त प्रयास किया गया था'। अंधेरा हो जाने के बाद, पेशवा की सेनाओं का आक्रमण कुछ हल्का पड़ा और कंपनी के सैनिकों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी उपलब्ध हो गया। जल्दी ही गोलीबारी बंद हो गई और अगली सुबह तक पेशवा की सेना का कहीं अतापता नहीं था। सुबह कैप्टन स्टॉन्टन ने अपने सिपाहियों से उन लोगों पर गोलियां चलाने को कहा जो 'गांव के आसपास भटक रहे थे।' पेशवा की सेना अंधेरे का लाभ उठाकर पीछे हट गई थी। कैप्टन स्टॉन्टन घायलों को अपने साथ लेकर अगली सुबह सिरूर पहुंच गए। कंपनी के 175 सैनिक मारे गए जबकि पेशवा की सेना के पांच-छः सौ सैनिकों ने अपनी जानें गवांई।

कोरेगांव की विरासत

बाद में कोरेगांव के युद्धक्षेत्र में कंपनी सेना की इस सफलता की याद में एक 60 फीट ऊँचा स्मारक स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ के चारों ओर लगी संगमरमर की पट्टिकाओं पर अंग्रेजी और मराठी में लिखा हुआ है, 'पूर्व में ब्रिटिश आर्मी के सबसे गौरवपूर्ण विजय अभियानों में से एक की याद में'। परंतु इस स्मारक का आज अंग्रेजों के लिए तो छोडिए, उनके पूर्व शासितों के लिए भी कोई महत्व नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस स्मारक पर उत्कीर्ण मृतक सैनिकों के नामों में से कम से कम 20 का अंत 'नैक' से होता है दृ इस्नैक, राईनैक, गुननैक आदि- ये वे नाम हैं जो 'अछूत' महार और मांग सैनिकों के थे। अपनी पुस्तक 'द ट्राईब्स एंड कास्टस ऑफ द सेन्ट्रल प्राविंसेस ऑफ इंडिया' (1916) में सेन्ट्रल प्राविंसेस के नृवंशविज्ञान के अधीक्षक आर. व्ही. रसल, पेशवाओं के राज में सामान्य लोगों के जीवन की झलक दिखलाते हैं। वे लिखते हैं, 'बंबई में किसी महार को सड़क पर थूकने की इजाजत भी नहीं थी ताकि कहीं ऐसा न हो कि किसी हिन्दू का पैर उस थूक पर पड़ जाए और वो प्रदूषित हो जाए। इसलिए महारों को अपने गले में एक मटकी लटकाकर चलना पड़ता था, जिसमें वे थूकते थे। उन्हें अपने पीछे कांटों भरी पेड़ की एक डाल घसीटते हुए चलना पड़ता था ताकि उनके कदमों के निशान सड़क से मिट जाएं। जब कोई ब्राम्हण दिखलाई देता था तो उन्हें उससे कुछ दूरी पर मुंह के बल जमीन पर लेट जाना पड़ता था ताकि उनकी छाया तक ब्राम्हण पर न पड़ सके। अगर किसी महार या मांग की छाया भी ब्राम्हण पर पड़ जाती थी तो वह तब तक न तो खाना खाता था और न पानी पीता था जब तक कि वह स्नान करके अपनी अशुद्धि को दूर न कर ले।'

आश्चर्य नहीं कि कोरेगांव को आज एक ऐसे युद्ध के लिए याद किया जाता है ,जहां ब्रिटिश कमान में मुट्ठी भर महारों ने पेशवाओं द्वारा स्वीकृत क्रूर ब्राह्मणवादी दमन का अंत किया था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय मध्यभारत में इधर से उधर भागते फिरे और अंततरु उन्होंने इंदौर के पास महू में 3 जून 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें कानपुर के निकट बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। 'कोरीगांम' शब्द और स्मारक स्तंभ को 2/1 बाम्बे नेटिव लाईट इंफेन्ट्री, जो आगे चलकर भारतीय सेना की महार रेजीमेंट बनी, के चिन्ह में शामिल किया गया। बाद में महार रेजीमेंट ने काठियावाड़ (1826), मुल्तान (1846) व द्वितीय अफगान युद्ध (1880) में अपना पराक्रम दिखाया। परंतु 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सैनिक विद्रोह में महार रेजीमेंट के कुछ सिपाहियों की हिस्सेदारी के कारण महारों की सेना में भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अक्टूबर 1910 में बंबई के गर्वनर की कार्यकारी समिति के सदस्य आर. ए. लैम्ब ने डिप्रेस्ड क्लासिस मिशन द्वारा संचालित एक स्कूल के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, 'कई महारों ने यूरोपीयनों व उन भारतीयों, जो अछूत नहीं थे, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाईयां लड़ीं और उनमें घायल हुए व मारे गए।' उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि 'एक सम्मानीय पेशे के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं।

-https://www.forwardpress.in/2015/01/maharon-aur-mangon-ke-hathon-peshwai-ka-ant/

***

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

Contd. from page 8

Save Reservation Rally ...

rise

10. All India Judicial Services to be created

11. Reservation in Jammu and Kashmir by removing Article 370

12. Ownership rights for land allotted under 20-point program in Delhi

13. Start a SC/ST bank with capital of Rs. 1 lac crore

14. Should be ensured that loan facility at each branch to SC/ST be given to make Stand Up India successful.

15. Procurement Policy it to be implemented in latter and spirit

16. SC/ST Hub Scheme to be made more effective and result oriented.

17. The space should be allotted to all Redi Patri vendors

The leader who made the Rally successful are – From Delhi - Om Prakash Singhmar, Parmendra, Sabir Khan, Bijendra Yadav, M.S. Lakra, Devi Singh Rana, N.D. Ram, Sanjay Raj, C. P. Soni, Dr. Rajpal, Satya Narayan, Indresh Sonkar, Bhanu Punia, Ravindra Singh, Y. K. Anand, R. S. Hans, Hari Prakash, Babu Lal, Ram Kumar, Sagar Yadav, S. P. Verma, Sudesh Yadav, Manish Suryavanshi, Mukesh Kumar, Dayanand, Mahendra Singh, Karam Chand, Daya Ram, Ravindra Kataria, Khem Chand, Vinod Rajaura, Sat Prakash, Ashok Kumar, Vijendra Singh, Babu Lal, M.R. Chaudhary, Dharam Singh, B.P. Singh, Onkar Singh, Dr. R. K. Govil, Devendra, Vijay, Sushil Khatik, Sumit Kumar, Madan Lal, Kaushlendra khateria, Ramnath, Fakir Chand, R. K. Varun, Hemant Kumar (IGL), Sanjeev Dohre, Shashank, Dr. S. L. Sagar, Vijay Ken, Sanjay, Pradeep (Bhim Army), Taraspal Tomar, Kaliram Tomar, Jai Kumar, Ram Niwas Chandravanshi, Anand, Haridas Valmiki, Mukesh Pahalwan, Dr. Chand Ram Arya, Ram Vilas Ram, Babu Lal Baswala, Dharam Pal Bhilware, Chunni Lal, Ashok Ahlawat, Ashok Luhera, Bhupendra Singh Kirar, Buddh Ratan, **Mahila Parisangh** – Savita Kadiyan Panwar, Sunita Ken, Sunita Gola, Urmila Kachchhap, Sangita Ravi, Usha Madhusudan, Mamta Gedam, Phoolmati, Rajkumari, Sunita Ken, Sarita Singhal, Mahalakshmi, Rinki Sagar, Rajni Dangi, Pushpa Koli, Asha Verma, Renu Saini, Rekha, Rita Sarkar, Rama, Lalita, Dr. Ruchita Pal, Kamlesh Kumari, Anjum Khan, Babita Kilsan, Gita Ahsiwal, Gauri Abhipuria, Mamta Rani, Safali, Dr. D.C. Barua, **Haryana –** S. P. Jarawata, Vishwanath, Mahasingh Bhurania, Satyavan Bhatia, Rajender Jogpal, Rajender Kumar, Dr. Shiv Kumar, Mahesh Datt, Wazir Singh Mehra, Raj Kumar, Dr. Mukhtiyar Singh, Sadhu Singh, Ashish Bhukal, Prof. Ravi Mahendra, Sunita Ken, Dilip Jatav, **U.P. –** Shushil Kamal, Neeraj Chak, R.K. Verma, D.K. Singh, Kalpendra Bharti, Rajesh Verma, Naresh Raj, Jai Prakash, Balram Chak, Bhojraj, Hari Kishan Bharti, **Chhattisgarh –** Harsh Meshram, Pradeep Sukhdeve, C. R. Jagade, **Maharashtra –** Siddharth Bhojane, Sanjay Kambale, Sunil Jode, Chandrashekhar Dongare, Udho Mule, Jivan Ramteke, Jugal Kishor Baghel, G.L. Balai, Harshvardhan Davane, Balaji Kondamangal, Ravi Suryavanshi, Sanghratna Nivdange, Ajit Kamble, Swapnil Kamble, Prof. Satish Wagare, Swapnil Mule, Ganeshraj Yerekar, Prakash Deepake, Akshay Manvar, Dinesh Bhagat, Mangesh Gadge, Abhijit Waghmare, Pradeep Gaikwad, **Karnataka –** J. Srinivaslu, Thippes, Santosh Lohar, Shiv Kamble, Sunil Waghmare, Uttam Sutar, Prakash Bhangare, **Tamilnadu –** S. Karuppaiyah, D. Ravichandran, K. Ravichandran, P.N. Perumal, Srinivasan, C.T. Prabhakaran, **West Bengal –** P. Bala, Subrata Batul, Sadan Naskar, Manimohan Biswas, Hari Bhai, Sachit Kumar Das, **J&K –** R. K. Kalsotra, B.L. Bhardwaj, Najir Chaudhari, **Punjab –** Tarsem Singh Gharu, Rohit Sonkar, Narender Singh, Mahender Singh, **Kerala –** K. T. Jonson, Smt. Joseph, **Madhya Pradesh –** Param Hans Prasad, Vipin Toppo, Narendra Chaudhary, Ashish Raipuriya, H. R. Chauhan, Suresh Kumar Rajaura, G.P. Nanhet Bauddh, Pratap Singh Ahirwar, Sachin Patel, Rajendra Nargaove, Prakash Ahirwar, Banti Ahirwar, Sushil Barkhane, Dinesh Kumar, **Uttarakhand –** Vijay Raj Ahirwar, Hira Lal, C. P. Singh, Mahabir Singh, Nitin Lamia, **Gujrat –** Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni, N.J. Parmar, Babu Lal Khatik, **Andhra Pradesh –** B. Das, **Telangana -** K. Maheshwar Raj, **Odissa –** Alekh Mallik, Dilip Kumar Behera, Narayan Das, G. R. Naik, Praveer Patro, Abhiram Naik, Sonu Anugud, **H.P. –** Sita Ram Bansal, Vikasdeep, **Manipur –** Madhu Chandra, Rev. Langhu Hileri, **Jharkhand –** Madhusudan Kumar, Welfred Kerketta, Jagaram, Pankaj Paswan, Urmila Kachchhap, Sangita Ravi, D. P. Lala, Anil Kumar, **Bihar –** Madan Ram, Shivdhar Paswan, Shivpujan, Bhagirathi Ram, Ajay Paswan, Amar Jyoti, Vikas Kumar, **Rajasthan –** Mukesh Meena, M.L. Rasu, Pancham Ram, Nandlal Bauddh, Saurabh Mahamna, Chiranjilal, Manohar Lal Samaria, Rajesh Lohia, Laxman Meena, Lokesh Meghwal, Ramesh Chauhan, Ashok Kumar, Chhagan etc..

***

Monument at Koregaon

Maharashtra battlefield is a reminder: Caste stereotypes of valour are misplaced.

Raja Sekhar Vundru

On January 1, 1927, a young Bhimrao Ambedkar visited the Bhima-Koregaon war monument on the banks of the Bhima near Pune with Dalit veterans and serving soldiers of the British Army. He was then celebrating the 109th year of victory of Dalit Mahar soldiers, who formed the majority of the British Army unit that fought against the Peshwas in the battle of Koregaon. This was one of the greatest instances of Dalit martial valour in their time with the British Army. Now, as we mark the 200th anniversary of the battle, it brings political significance and cultural assertion as lakhs of people visited the war monument, rekindling Dalit pride and denouncing inequality.

The Battle of Koregaon became a part of folklore, serving as an example of Mahar Dalit valour. Ardythe Basham, in her University of British Columba doctoral thesis (1985), writes: "A small force of 500 men... under the command of Captain F.F. Staunton [who] fought without rest or respite, food or water continuously for twelve hours against a large force of 20,000 Horse and 8,000 Infantry of Peshwa Baji Rao II". A significant portion of the British Army's 21st Regiment of the Bombay Native Infantry, which fought the battle, was comprised of Mahars. The names of the 21 Mahars who died in the battle were etched on the war monument. The battle was a turning point in the third Anglo-Maratha war, and established the British firmly on Indian soil.

The battle is a matter of pride for Dalits. The Peshwa rulers imposed the worst social conditions on untouchables, who were ordered to hang a pot around their necks to prevent their spit from falling on the ground, and to wear a broom around their waists to sweep the ground as they moved so they would not "pollute" it. This was depicted well in the 2012-film Shudra: The Rising. The defeat of these rulers was one of the greatest acts of revenge carried out by an oppressed community.

The Mahars' martial valour and military achievements go back to their presence in the armies of Chhatrapati Shivaji. Before 1857, Mahars formed about 25 per cent of the Bombay Army, and were a vital part of the British Marine Battalion. After the 1857 mutiny, the British believed that one of the reasons for the unrest was the inclusion of lower castes in the army. Recruits from the upper castes and the middle-caste peasantry protested the idea of saluting or taking orders from soldiers drawn from untouchable castes. The Vellore mutiny of 1801 and the 1857 mutiny have been documented as caste conflicts.

After the 1857 mutiny, and upon the recommendations of the Peel Commission, the British placed a ban on the recruitment of untouchables. Pre-Ambedkarite Mahar leaders repeatedly petitioned the British to reconsider the decision, and in a 1909 petition argued, "that if the government felt that caste prejudice was too deeply ingrained in the army to allow their employment alongside other castes, a separate Mahar company or battalion should be formed to circumvent this caste prejudice as with the Mazhabi Sikhs of the 23rd, 32nd, and 34th Pioneers".

The Mazhabi Sikhs (untouchables who converted to Sikhism) and Dalit Sikhs (Ramdasis and Ravidasis) had been placed in separate regiments to circumvent caste issues. The regiments were specially trained as assault pioneers, and helped the British regain Delhi and Lucknow during the 1857 mutiny. Untouchables made up a significant part of the Madras Army — Malas from Andhra Pradesh were also part of the Madras Army, and enlisted during the First and Second World Wars from Madras Presidency along with the Holeyas of Karnataka, who enlisted with Mahars in the Bombay Army.

Ambedkar's father and six uncles were subedar majors — the highest rank any native Indian could attain in the British Army. He married into an army family. After de-enlistment, Ambedkar used his lineage and knowledge of the sacrifices Dalit soldiers had made to question British apathy.

In a booklet distributed in 1930 during the First Round Table Conference in London, Ambedkar wrote, "Who were these people who joined the army of the East India Company and helped the British to conquer India? ...the people who joined the Army of the East India Company were the Untouchables of India. The men who fought with Clive in the battle of Plassey were the Dusads, and the Dusads are Untouchables. The men who fought in the battle of Koregaon were the Mahars, and the Mahars are Untouchables. Thus in the first battle and the last battle (1757-1818) it was the Untouchables who fought on the side of the British and helped them to conquer India. The truth of this was admitted by the Marquess of Tweedledale in his note to the Peel Commission which was appointed in 1859 to report on the reorganisation of the Indian Army."

He argued that the Bombay Army of Mahars and Madras Army of Pariahs helped the British quell the 1857 mutiny, and that "nothing can be more ungrateful than this exclusion of the Untouchables from the Army".

Due to Ambedkar's efforts, a separate Mahar Regiment, similar to that of the Mazhabi Sikhs, was created in 1941. A separate 1st Chamar Regiment was enlisted in 1943. The Mazhabi and Ramdasi Sikh regiments were merged in 1941, and in 1944 renamed as the Sikh Light Infantry. While the Mahar regiment and Sikh Light Infantry continue to serve the Indian nation even today, the Chamar Regiment was disbanded after World War II.

Ambedkar's campaign in the 1930s ensured political rights for untouchables. His campaign and confidence emanated from the great lineage and pride of untouchable valour, fearlessness and sacrifice. The 200-year mark of the battle of Koregaon is just a reminder to the nation that valour and sacrifice don't belong to a select group of castes.

- The writer is an IAS officer. His recent book is 'Ambedkar, Gandhi and Patel: The Making of India's Electoral System'.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/monument-at-koregaon-bhimrao-ambedkar-5007929/

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 4 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 January , 2018

Save Reservation Rally held in Delhi

This struggle will continue till the goal is achieved

Lacks of SC/ST/OBC gathered under the aegis of Confederation

The rally of All India Confederation of SC/St organizations held on 26Th December 2017 at Ramleela Ground was a historical one. This was the second largest rally after 11 December 2000. The gathering could have been much more if the rally was held on original date and that was 4th December 2017. This shows that confederation is getting strengthened day by day. The role of Social media has also added to it. Other reason was that dilution of reservation at all level. The youths and student are also charged to struggle for saving the reservation.

While addressing the rally, Dr. Udit Raj, National Chairman of the Confederation said that continuous attempts are being made to finish reservation under the garb of Privatization. Dalits and backwards have been suffering from backwardness and slavery for more than thousands of years. Today, we are all citizens of an independent India, but still there has not been much change in the social life of SC/ST and OBC.

It's unfortunate that India is not only most unequal socially but economically also. A few are getting richer and richer and majority of people are either job less or working on contract basis. The government departments are mad to go for contract system in employment and outsourcing of jobs and works have become the order of the day. This has adverse impact more on SC/ST/OBC since they don't have other avenues. Any democratic government postulates welfare activism and hence the most important job of any government is to provide maximum employment to its citizen.

Dr. Udit Raj further spoke that reservation is often considered to be bottle neck in the development of the nation but it is completely unfounded and mistaken. Mysore and Kerala got reservation in 1935, and the Justice Party secured reservation in Tamil Nadu in 1921. The estate of Kohlapur currently Maharashtra was blessed with reservation upto 50% in 1902 and these above 4 states are better developed than Northern States at many index. The time has come for the so called upper caste brothers and sisters to introspect themselves that SC/ST and OBC are part of their society only. Inclusion of these people in various walks of life will strengthen the country in all ways and means. How can about 20% population only aggrandised to have buying power, can help in production and purchases. By including these marginalised people through reservation, more number of people will have purchasing power which will resultantly increase the demands. Increasing the demands of various goods and services is to contribute to higher GDP and the corporate houses will be gainer. To dispel the myth of merit that through reservation inefficiency is promoted but a study by Prof. Ashwani Deshpande in coordination with Michigan University of America has found that higher participation of SC/ST employees like in railways has led to higher efficiencies. In these contexts so it is not only in the interest of SC/ST/OBC to provide reservation but of whole nation. Dr. Udit Raj has introduced a Private Member Bill in the Parliament for Reservation in Private Sector and it has been urged in the rally that the government should convert it into Government Bill and amend the Constitution to fulfil the demand.

Ever since privatization began, mainly SCs and STs have started getting alienated not only from governance but also from economic activities. The Courts have been very ruthless towards these communities; the rights provided by legislatures are being continuously diluted by the judiciary. For instance, it was the Vajpayee Government which made 81st, 82nd and 85th Constitutional Amendments. The 85th Amendment pertains to reservation in promotion – this Amendment was litigated in the Supreme Court in 2006; the case is known as Nagaraj case. The 5 judges' bench finally validated the 85th Amendment and placed certain conditions which were uncalled for, for example, reservation in promotion will be given only when backwardness of SCs and STs is tested again and again, there is no inadequate representation and it does not hamper efficiency of administration. As far as testing the backwardness is concerned, the moment SCs and STs are included in Articles 341 and 342 of the Indian Constitution, it is done so only because they are backward. Their backwardness is tested by Registrar General of India, National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes.In December 2012, a Bill was passed to give reservation in promotion in Rajya Sabha, doing away with the anomalies created by Courts, but was unsuccessful in Lok Sabha. It was unequivocally passed in the rally today that the government should pass this bill in this winter session to remove all hinderances in reservation in promotion.

Dr. Udit Raj lamented that the workers are heavily exploited under the contract system, whether they are teachers, employees, class IV employees or cleaners. In the private sector, wages are paid in cash – workers are never paid the full amount due to them. The Government must exercise a check on this practice and ensure that salaries are paid directly in bank accounts – the main beneficiaries of this will be Dalits and OBCs.

Main demands of the Confederation

1. Reservation in promotion and in private sector
2. Enact Reservation Act
3. Reservation in higher judiciary and armed forces
4. Ban recruitment in contract system
5. Special recruitment drives to fill backlog posts and vacant posts
6. Free and equal education, and land to the landless
7. Law for implementation of SCP and TSP
8. Caste certificate of one state made valid in all states
9. Increase in educational scholarships in line with price

Contd. on page 7

Mrs. Seema Raj, Narendra Chaudhary, Param Hans Prasad,Ramubhai Vaghela,Savita Kadiyan Panwar, Satya Prakash Jrawata, Er. Jugal Kishore Baghel, Sanjay Kamble, P.Bala, K.Maheshwar Raj, S. Karuppaiah, Siddarth Bhojane, Tashem Singh Gharu, Y.K. Anand, Babulal, Back Side- Sheodhar Paswan, Dhyan Singh,G.R. Naik, Utpal Kulkarni, Harsh Meshram, Ashok Luhera, Sadhu Singh etc.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar